(d) the steps taken by Government to resolve the issues involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) Sir, Groups 'B* and *C officers of the Central Excise, Customs and Income Tax were on strike from 10th November, 1998 to 12th November, 1998. But international air-ports, major and minor ports and cargo complexes were not paralysed.

(c) The employees were demanding higher pay scales and improvement in some of the service conditions. The strike did not lead to any loss, of revenue.

(d) The demands are being examined.

IDBI's tie up with us based principal financial group

2533. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India (IDBI) is considering a proposal to tie up with the US based Principal Financial Group for management of Provident and Pension Funds in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that Principal Financial Group, a leading provider of pension products based in the United States has held preliminary discussions with IOSI Capital Market Services Ltd., a subsidiary of IDBI to Explore the possibility of a tie up for management of provident and pension funds in India.

न्यु इंडिया एश्योरेंस कम्पनी की स्वायत्तता

2543. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के आधिकारियों ने साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) से स्वायत्तता की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्होने आरोप लगाया है कि साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) के नियंत्रण में कार्य करते हुए इनकी कम्पनी को घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उक्त मांग पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में बीमा क्षेत्र में प्रीमियम की राशि बहुत कम है; और

(ड) यदि हां, तो सरकार भारत में बीमा प्रीमियम कि राशि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दन): (क) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि अधिकारी संघ ने कलकत्ता में हाल में सम्पन्न विचारगोष्ठी में कम्पनी को स्वायत्ता प्रदान करने सम्बन्धी मांग को सामने रखा था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। न्यू इंडिया द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह गलत है और इस बयान का कोई आधार नहीं है।

(घ) और (ड) देश में व्याप्त संभाव्यता की तुलना में साधारण बीमा क्षेत्र में प्रीमियम की राशि कम है। देश में बीमा प्रीमियम कि राशि मे वृद्धि करने के लिए लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने,बीमा प्रभाव बढ़ाने, बोर्ड द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा, उत्पादों के नई तरीकों, नयी सूचना प्रोद्योगिकियों को अपनाने आदि जैसे कई उपाय किए जा रहे है।

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को लोकल एरिया बैंक खोलने की अनुमति

2535. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पी. एच. डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने यह अनुरोध किया है कि "ए" क्रेडित रेटिंग से सम्पन्न नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को लोकल एरिया बैंक खोलने के अनुमति मिलनी चाहिए;